प्रेषक,

पी०सी० शर्मा, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः १३ जून, 2011

विषय:-लैंको हाइड्रो एनर्जीज प्रा० लि० को ग्राम ब्यूंग एवं रामपुर, तहसील ऊखीमठ, जिला रूद्रप्रयाग में, जल विद्युत परियोजना हेत् 1.399 है० भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या—809/26—6/2009—10, दिनांक—7.12.2009 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, लैंको हाइड्रो एनर्जीज प्रा0 लि0 को ग्राम ब्यूंग एवं रामपुर, तहसील ऊखीमठ, जिला रूद्रप्रयाग में, जल विद्युत परियोजना हेतु 1.399 है0 भूमि क्य की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नितिखित शर्ती/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी रिथित हो, की अनुमित से ही

भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (जल विद्युत परियोजना का निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा—167 के परिणाम लागू होंगे।

4— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति / जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति / जनजाति के भूमिधर होने की रिथति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित 5— जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6— शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7— संस्था द्वारा ऊर्जा विभाग/अन्य सम्बन्धित विभागो से यथा आवश्यक नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करते हुए, परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— सम्बन्धित इकाई द्वारा भू—उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

9— किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमित नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

10— भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों / संस्थाओं से विधिक व अन्य

अनापत्तियाँ / स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

12— उपरोक्त प्रतिबन्धों / शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उचयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में,जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा) प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०- 11/2 / समदिनांकित / 2011

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
- 2— मुख्य राजस्य आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5— अधिकृत हस्ताक्षरी, लैंको हाइड्रो एनर्जीज प्रा० लि०, पंजीकृत कार्यालय 14—एच० , पुष्पांजलि एनक्लेव, जनरल महादेव सिंह रोड, देहरादून।
- 6— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 7- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सन्तोषं बडोनी)